भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2629

दिनांक 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम किया जाना

2629 श्री संजय सेठ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, क्या उपाय किए गए हैं/ कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को विशेष निधियों का कितना आवंटन किया गया और संवितरित की गई कुल राशि, इस आवंटन के मानदंड और इस आवंटन के माध्यम से वित्तपोषित किसी विशिष्ट परियोजना या सहायता कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को आवंटित विशेष निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): आपदा प्रबंधन की, क्षति के आकलन, राहत और शमन सहित प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है। देश भर में, उत्तर प्रदेश राज्य सहित, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए प्रमुख उपाय और कदम निम्नानुसार हैं: -

(i) 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (सीएपी)' का विभिन्न प्रसार माध्यमों, जैसे, एसएमएस, टीवी, रेडियो, भारतीय रेलवे, कॉस्टल सायरन, सेल प्रसारण, इंटरनेट (आरएसएस फ़ीड और ब्राउज़र अधिसूचना), गगन और नाविक के उपग्रह रिसीवर आदि, का उपयोग कर और सभी चेतावनी एजेंसियों के एकीकरण के माध्यम से, सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में भारत के नागरिकों को आपदाओं से संबंधित भू-लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों / अलर्टों के प्रसार के लिए कार्यान्वयन किया गया है।

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2629

भू-लक्षित क्षेत्रों में चेतावनियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में भेजी जाती हैं। चेतावनियों का अनुमोदन देने/संपादित करने और उनके प्रसार के लिए मीडिया चुनने के लिए आपदा प्रबंधकों हेतु एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। हाल की आपदाओं में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इस प्रणाली का उपयोग करके अब तक 4300 करोड़ से अधिक अलर्ट प्रसारित किए जा चुके हैं।

(ii) प्रधानमंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल आपातकालीन नंबर' के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, मौजूदा एकल नंबर "112" के साथ "ईआरएसएस का विस्तार" परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, जो आपदाओं से संबंधित आपातकालीन कॉल को भी पूरा करता है। इस परियोजना को आपदा से संबंधित आपातकालीन कॉलों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।

(iii) आपदा मित्र योजना को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में कार्यान्वयन किया गया है और 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को बाढ़ सहित आपदा बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(iv) भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (IUINDRR) की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के तत्वावधान में, आपदा रेज़ीलिएस में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की भूमिका को उजागर करने के साथ डीआरआर के लिए मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने और विभिन्न स्तरों पर इसके एकीकरण के लिए की गई है। IUINDRR शिक्षा और नीति के बीच इंटरफेस के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ज्ञान उत्पादों के सहयोगात्मक विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब तक 300 से अधिक विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क में शामिल हुए हैं।

(v) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) को जिला स्तर तक आपदा से होने वाले नुकसान पर क्षेत्रवार डेटा एकत्र करने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (SFDRR) के विभिन्न लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास हेतु शुरू किया गया है।

(vi) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपदा प्रबंधन/मोचन के विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर सभी 36 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और रासायनिक, जैविक,

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2629

रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) के संबंध में सामुदायिक आपदा जागरूकता पर नियमित रूप से मॉक अभ्यास संचालित करता है। एनडीआरएफ भारत के सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के असुरक्षित विद्यालयों में बच्चों को आपदा मोचन पर प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) भी संचालित करता है।

(vii) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) द्वारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक बाढ़ संवेदनशील राज्यों के लिए और जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस विकसित किया गया है।

(viii) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (BMTPC) ने एक डिजिटल एटलस विकसित किया है जो देश के विभिन्न हिस्सों की विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

(ix) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) सभी प्रभावित/संभावित प्रभावित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चक्रवात सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है।

(x) आम लोगों तक प्रारंभिक चेतावनियाँ और अलर्ट को समय पर प्रसारित करने के लिए कई नए मोबाइल एप्लिकेशन जैसे दामिनी, मौसम, सचेत आदि विकसित किए गए हैं।

(ख) से (ग): पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) का प्रावधान किया था और इसके तहत वर्ष 2025-26 तक की पंचाट अवधि के लिए 13,693 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसी प्रकार, XV-FC ने राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का भी प्रावधान किया और इसके तहत शमन उपायों के उद्देश्य के लिए 32,031 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश क्रमशः दिनांक 14.01.2022 और दिनांक 28.02.2022 को तैयार किए थे। ये दिशानिर्देश वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

एनडीएमएफ / एसडीएमएफ के तहत, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली बाढ़ सहित सभी अधिसूचित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से निधि दी गई है।

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2629

राज्य सरकारें बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ़ सहित सभी अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत उपायों हेतु एसडीआरएफ / एनडीआरएफ के अंतर्गत सभी राज्यों को जारी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	एसडीआरएफ का आवंटन	जारी किया गया केंद्रीय शेयर	एनडीआरएफ
2020-21	23186.40	17825.63	8257.11
2021-22	23186.40	17747.20	7342.30
2022-23	24344.80	16392.80	1524.854
2023-24	25565.60	19419.60	869.14
2024-25	26841.60	15823.20	4808.32
(अब तक)			

बाढ़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एफएमबीएपी को मंजूरी दी है।

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2629

उत्तर प्रदेश सरकार की कुल 29 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनकी अनुमानित लागत 959.27 करोड़ रुपये है। एफएमपी घटक के तहत 470.19 करोड़ रुपये और बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के तहत 222.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को जारी की गई है।

इसके अलावा पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा तीन महानगरों (मुंबई, चेन्नई और कोलकाता) के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु एकीकृत समाधान तैयार करने और चार शहरों (बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे) के लिए शहरी बाढ़ को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के अंतर्गत 2025-26 तक की अवधि हेतु 2,500 करोड़ रुपये के आवंटन की भी सिफारिश की गई है। अब तक स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

शहर/राज्य	स्वीकृत परियोजना राशि	जारी पहली किस्त
बेंगलुरु/कर्नाटक	275.00	71.62
चेन्नई/तमिलनाडु	561.29	114.75
हैदराबाद/तेलंगाना	319.53	75.00
कोलकाता/पश्चिम बंगाल	650.43	150.00
पुणे/महाराष्ट्र	286.69	75.00
मुंबई/महाराष्ट्र	707.71	150.00
अहमदाबाद/गुजरात	275.00	-